

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

### ज्ञा प न

कमांक B/3108 /  
तीन-8-6/23 भाग-14

जबलपुर, दिनांक : 25 अप्रैल, 2023

प्रति,

प्रधान

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के सगरत
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के सगरत
3. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
4. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
6. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
7. सहायक(यात्रा भत्ता)/यात्रा भत्ता लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
8. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

विषय : स्थानांतरण यात्रा भत्ता देयक के संबंध में।

उपरोक्त विषय में आपकी ओर म.प्र.शासन, विधि विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 15.6.2006 की कंडिका-13 व भारत सरकार के मेमोरेण्डम दिनांक 13 जुलाई 2017 और भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.03.2021 की छायाप्रतियां प्रेषित कर यथानिर्देशित लेख है कि म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 15.6.2006 की कंडिका-13 के अनुसार प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को, स्थानांतरित किये जाने पर, भारत सरकार के नियमानुसार, स्थानांतरण अनुदान देय है। भारत सरकार के मेमोरेण्डम दिनांक 13 जुलाई 2017 में सातवें वेतन आयोग लागू होने पर दिनांक 01.07.2017 में स्थानांतरण अनुदान के रूप में एक माह के मूल वेतन का 80 प्रतिशत की राशि स्थानांतरण अनुदान देना है एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.03.2021 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि माननीय न्यायाधिपति महोदयों को स्थानांतरण पर एक माह के मूल वेतन की 80 प्रतिशत राशि स्थानांतरण अनुदान के रूप में देने के निर्देश है। न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण किये जाने पर उन्हें केन्द्र शासन के नियमानुसार वर्तमान में एक माह के मूल वेतन की 80 प्रतिशत की राशि स्थानांतरण अनुदान के रूप में प्राप्त करने की पात्रता आती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(विकास चंद्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन).

25/4/23

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

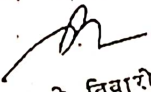
आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2006

फा.कमांक 3(ए)19/03/21-ब(एक), राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटी.(सिविल) कमांक 1022/89 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 21 फरवरी, 2006 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 5 जून, 2006 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1.11.1999 से निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान करता है:-

## 1. जल एवं विद्युत प्रभार

- (1) विद्युत प्रभार - कुल प्रभार की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा प्रतिमाह रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) के अंतर्गत सरकार द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्य को देय होगी।
- (2) जल प्रभार - कुल प्रभार की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा प्रतिमाह रूपये 100/- (रूपये एक सौ) के अंतर्गत सरकार द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्य को देय होगी।
- (3) उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति न्यायिक सेवा के सदस्य द्वारा प्रभार शुल्क की रसीद जिला एवं सेशन न्यायाधीश/विभाग प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करने पर त्रैमासिक देय होगी।
- (4) विद्युत एवं जल शुल्क की दरों में परिवर्तन होने पर अधिकतम सीमा के संबंध में समय-समय पर संशोधन समाविष्ट किया जा सकेगा।
- (5) न्यायिक सेवा का जो सदस्य अपने पति/पत्नी को आवंटित शासकीय आवासगृह में अथवा निजी आवास में रहते हैं, में से किसी एक को ऐसे व्यय से छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (6) दिनांक 1.11.1999 से भुगतान प्रारंभ किये जाने की दिनांक तक के एरियर्स का भुगतान रसीद/प्रमाणक प्रस्तुत किये जाने पर अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जावेगा। परन्तु यदि ऐसी रसीद या प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भुगतान औसत रूप से विद्युत व्यय के लिये रूपये 200/- (रूपये दो सौ) प्रतिमाह तथा जल व्यय के लिये रूपये 10/- (रूपये दस) प्रतिमाह की दर से किया जावेगा।

  
वी. वी. तिवारी  
प्रमुख सचिव (विधि)

11. समवर्ती प्रभार भत्ता

अपने न्यायालय के अतिरिक्त, अन्य न्यायालय का, लगातार दस कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये, प्रभार प्राप्त करने वाले न्यायाधीश द्वारा, यदि ऐसे न्यायालय का पर्याप्त न्यायिक कार्य, निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे न्यायाधीश को, अतिरिक्त प्रभार के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के, वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि, अतिरिक्त प्रभार भत्ता के रूप में देय होगी।

12. अवकाश नगदीकरण तथा अवकाश वेतन

1. न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को, दो वर्ष के अंतराल में, एक माह की अवधि का अवकाश, नगदीकरण कराने की पात्रता होगी।

2. न्यायिक सेवा के सदस्य को, अवकाश नगदीकरण कराने से प्राप्त राशि करमुक्त होगी।

3. अवकाश नगदीकरण की उक्त सुविधा सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली सुविधा के अतिरिक्त होगी।

4. न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को, अर्जित अवकाश टाने के लिये बाध्य नहीं किया जावेगा।

13. स्थानांतरण अनुदान / विस्थापन अनुदान

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को, स्थानांतरित किये जाने पर, भारत सरकार के नियमानुसार, स्थानांतरित स्थान की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक होने की दशा में, एक माह के मूल वेतन के बराबर राशि, तथा 20 किलोमीटर से कम दूरी की स्थिति में, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, एक माह के मूल वेतन की 1/3 (तिहाई) के बराबर धनराशि, स्थानांतरण अनुदान के रूप में, स्थानांतरण भत्ते के अतिरिक्त देय होगी।

14. आवास किराया भत्ता

1. उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय, के न्यायाधीशों को, जिस तरह निःशुल्क प्रभार के साथ आवास उपलब्ध कराया जाता है, उसी तरह न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को, प्राथमिकता के आधार पर, उनकी पात्रता के अनुरूप, निःशुल्क प्रभार के साथ, कार्यालयीन आवासगृह, राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

पी. पी. तिवारी

New Delhi, the 13<sup>th</sup> July 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Travelling Allowance Rules - Implementation of the Seventh Central Pay Commission.

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Travelling Allowance entitlements to civilian employees of Central Government, President is pleased to decide the revision in the rates of Travelling Allowance as set out in the Annexure to this Office Memorandum.

2. The 'Pay Level' for determining the TA/DA entitlement is as indicated in Central Civil Service (Revised Pay) Rules 2016.
3. The term 'Pay in the Level' for the purpose of these orders refer to Basic Pay drawn in appropriate Pay level in the Pay Matrix as defined in Rule 3(8) of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 and does not include Non-Practising Allowance (NPA), Military Service Pay (MSP) or any other type of pay like special pay, etc
4. However, if the Travelling Allowance entitlements in terms of the revised entitlements now prescribed result in a lowering of the existing entitlements in the case of any individual, groups or classes of employees, the entitlements, particularly in respect of mode of travel, class of accommodation, etc., shall not be lowered. They will instead continue to be governed by the earlier orders on the subject till such time as they become eligible, in the normal course, for the higher entitlements.
5. The claims submitted in respect of journey made on or after 1<sup>st</sup> July, 2017, may be regulated in accordance with these orders. In respect of journeys performed prior to 1<sup>st</sup> July, 2017, the claims may be regulated in accordance with the previous orders dated 23.09.2008.
6. It may be noted that no additional funds will be provided on account of revision in TA/DA entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements.
7. These orders shall take effect from 01<sup>st</sup> July, 2017
8. Separate orders will be issued by Ministry of Defence and Ministry of Railways in respect of Armed Forces personnel and Railway employees, respectively
9. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India

Hindi version is attached.



(Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to: C&AG and U.P.S.C., etc. as per standard endorsement list.

Annexure to Ministry of Finance, Department of Expenditure  
O.M.No.19030/1/2017-E.IV dated 10<sup>th</sup> July 2017.

In supersession of Department of Expenditure's O M No. 19030/3/2008-E.IV dated 23.09.2008, in respect of Travelling Allowance the following provisions will be applicable with effect from 01.07.2017 :

2. Entitlements for Journeys on Tour or Training

A.(i) Travel Entitlements within the Country

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
14 and above	Business/Club class by air or AC-I by train
12 and 13	Economy class by air or AC-I by train
6 to 11	Economy class by air or AC-II by train
5 and below	First Class/AC-III/AC Chair car by train

(ii) It has also been decided to allow the Government officials to travel by Premium Trains/Premium Tatkal Trains/Suvidha Trains, the reimbursement to Premium Tatkal Charges for booking of tickets and the reimbursement of Dynamic/Flexi-fare in Shatabdi/Rajdhani/Duronto Trains while on official tour/ training. Reimbursement of Tatkal Seva Charges which has fixed fare, will remain continue to be allowed. Travel entitlement for the journey in Premium/Premium Tatkal/Suvidha/ Shatabdi/Rajdhani/ Duronto Trains will be as under :-

Pay Level in Pay matrix	Travel Entitlements in Premium/Premium Tatkal/Suvidha/ Shatabdi/ Rajdhani/ Duronto Trains
12 and above	Executive/AC 1 <sup>st</sup> Class (In case of Premium/Premium Tatkal/Suvidha/Shatabdi/Rajdhani Trains as per available highest class)
6 to 11	AC 2 <sup>nd</sup> Class/Chair Car (In Shatabdi Trains)
5 & below	AC 3 <sup>rd</sup> Class/Chair Car

(iii) The revised Travel entitlements are subject to following -

- (a) In case of places not connected by rail, travel by AC bus for all those entitled to travel by AC II Tier and above by train and by Deluxe/ordinary bus for others is allowed.
- (b) In case of road travel between places connected by rail, travel by any means of public transport is allowed provided the total fare does not exceed the train fare by the entitled class.
- (c) All mileage points earned by Government employees on tickets purchased for official travel shall be utilized by the concerned department for other official travel by their officers. Any usage of these mileage points for purposes of private travel by an officer will attract departmental action. This is to ensure that the benefits out of official travel, which is funded by the Government, should accrue to the Government.
- (d) In case of non-availability of seats in entitled class, Govt. servants may travel in the class below their entitled class.

B. International Travel Entitlement :

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
17 and above	First class
14 to 16	Business/Club class
13 and below	Economy class

C. Entitlement for journeys by Sea or by River Steamer

(i) For places other than A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of Island :-

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
9 and above	Highest class
6 to 8	Lower class if there be two classes only on the steamer
4 and 5	If two classes only, the lower class. If three classes, the middle or second class. If there be four classes, the third class
3 and below	Lowest class

(ii) For travel between the mainland and the A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of Island by ships operated by the Shipping Corporation of India Limited :-

Pay Level in Pay Matrix	Travel entitlement
9 and above	Deluxe class
6 to 8	First/ 'A' Cabin class
4 and 5	Second/ 'B' Cabin class
3 and below	Bunk class

D. Mileage Allowance for Journeys by Road :

(i) At places where specific rates have been prescribed :-

Pay Level in Pay Matrix	Entitlements
14 or above	Actual fare by any type of public bus including AC bus OR At prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC taxi OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped, etc.
6 to 13	Same as above with the exception that journeys by AC taxi will not be permissible
4 and 5	Actual fare by any type of public bus other than AC bus OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motor cycle, moped, etc.
3 and below	Actual fare by ordinary public bus only OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by autorickshaw, own scooter, motor cycle, moped, etc.

(ii) At places where no specific rates have been prescribed either by the Directorate of Transport of the concerned State or of the neighboring States:

For journeys performed in own car/taxi	Rs. 24/- per Km
For journeys performed by auto rickshaw, own scooter, etc	Rs. 12/- per Km

At places where no specific rates have been prescribed, the rate per km will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent.

## E(i). Daily Allowance on Tour

Pay level in pay matrix	Entitlement
14 and above	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹7,500/- per day. Reimbursement of AC taxi charges as per actual expenditure commensurate with official engagements for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding ₹1200/- per day.
12 and 13	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹4,500/- per day. Reimbursement of AC taxi charges of up to 50 km per day for travel within the city. Reimbursement of food bills not exceeding ₹1000/- per day.
9 to 11	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹2,250/- per day. Reimbursement of non-AC taxi charges of up to ₹338/- per day for travel within the city. Reimbursement of food bills not exceeding ₹900/- per day.
6 to 8	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹750 per day. Reimbursement of non-AC taxi charges of up to ₹225/- per day for travel within the city. Reimbursement of food bills not exceeding ₹800/- per day.
5 and below	Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to ₹450 per day. Reimbursement of non-AC taxi charges of up to ₹113/- per day for travel within the city. Reimbursement of food bills not exceeding ₹500/- per day.

(ii) **Reimbursement of Hotel charges** :- For levels 8 and below, the amount of claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of stay, name of dwelling, etc. Additionally, for stay in Class 'X' cities, the ceiling for all employees up to Level 8 would be ₹1,000 per day, but it will only be in the form of reimbursement upon production of relevant vouchers. The ceiling for reimbursement of hotel charges will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent

(iii) **Reimbursement of Travelling charges** :- Similar to Reimbursement of staying accommodation charges, for levels 8 and below, the claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of travel, vehicle number, etc. The ceiling for levels 11 and below will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. For journeys on foot, an allowance of Rs.12/- per kilometer travelled on foot shall be payable additionally. This rate will further increase by 25% whenever DA increases by 50%.

(iv) **Reimbursement of Food charges** :- There will be no separate reimbursement of food bills. Instead, the lump sum amount payable will be as per Table E(i) above and, depending on the length of absence from headquarters, would be regulated as per Table (v) below. Since the concept of reimbursement has been done away with, no vouchers will be required. This methodology is in line with that followed by Indian Railways at present (with suitable enhancement of rates), i.e. Lump sum amount payable. The lump sum amount will increase by 25 percent whenever DA increase by 50 percent.

## (v) Timing restrictions

Length of absence	Amount Payable
If absence from headquarters is <6 hours	30% of Lump sum amount
If absence from headquarters is between 6-12 hours	70% of Lump sum amount
If absence from headquarters is >12 hours	100% of Lump sum amount

Absence from Head Quarter will be reckoned from midnight to midnight and will be calculated on a per day basis.

(vi) In case of stay/journey on Government ships, boats etc. or journey to remote places on foot/mules etc for scientific/data collection purposes in organization like FSI, Survey of India, GSI etc., daily allowance will be paid at rate equivalent to that provided for reimbursement of food bill. However, in this case, the amount will be sanctioned irrespective of the actual expenditure incurred on this account with the approval of the Head of Department/controlling officer.

Note : DA rates for foreign travel will be regulated as prescribed by Ministry of External Affairs

### 3. T.A. on Transfer

TA on Transfer includes 4 components : - (i) Travel entitlement for self and family (ii) Composite Transfer and packing grant (CTG) (iii) Reimbursement of charges on transportation of personal effects (iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance

#### (i) Travel Entitlements :

- (a) Travel entitlements as prescribed for tour in Para 2 above, except for International Travel, will be applicable in case of journeys on transfer. The general conditions of admissibility prescribed in S.R.114 will, however, continue to be applicable.
- (b) The provisions relating to small family norms as contained in para 4(A) of Annexure to M/o Finance O.M. F.No. 10/2/98-IC & F.No. 19030/2/97-EIV dt. 171, April 1998, shall continue to be applicable.

#### (ii) Composite Transfer and Packing Grant (CTG) :

- (a) The Composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of the last month's basic pay in case of transfer involving a change of station located at a distance of or more than 20 kms from each other. However, for transfer to and from the Island territories of Andaman, Nicobar & Lakshadweep, CTG shall be paid at the rate of 100% of last month's basic pay. Further, NPA and MSP shall not be included as part of basic pay while determining entitlement for CTG.
- (b) In cases of transfer to stations which are at a distance of less than 20 kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.
- (c) In cases where the transfer of husband and wife takes place within six months, but after 60 days of the transfer of the spouse, fifty percent of the transfer grant on transfer shall be allowed to the spouse transferred later. No transfer grant shall be admissible to the spouse transferred later, in case both the transfers are ordered within 60 days. The existing provisions shall continue to be applicable in case of transfers after a period of six months or more. Other rules precluding transfer grant in case of transfer at own request or transfer other than in public interest, shall continue to apply unchanged in their case.

#### (iii) Transportation of Personal Effects

Level	By Train/Steamer	By Road
12 and above	6000 Kg by goods train/4 wheeler wagon/ 1 double container	Rs. 50/- per km
6 to 11	6000 Kg by goods train/4 wheeler wagon/ 1 single container	Rs. 50/- per km
5	3000 kg	Rs. 25/- per km
4 and below	1500 kg	Rs. 15/- per km

The rates will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. The rates for transporting the entitled weight by Steamer will be equal to the prevailing rates prescribed by such transport in ships operated by Shipping Corporation of India. The claim for reimbursement shall be admissible subject to the production of actual receipts/ vouchers by the Govt. servant. Production of receipts/vouchers is mandatory in r/o transfer cases of North Eastern Region, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep also.



Transportation of personal effects by road is as per kilometer basis only. The classification of cities /towns for the purpose of transportation of personal effects is done away with.

(iv) **Transportation of Conveyance.**

Level	Reimbursement
6 and above	1 motor car etc. or 1 motor cycle/scooter
5 and below	1 motorcycle/scooter/moped/bicycle

The general conditions of admissibility of TA on Transfer as prescribed in S.R. 116 will, however, continue to be applicable.

**4 T.A. Entitlement of Retiring Employees**

TA on Retirement includes 4 components :- (i) Travel entitlement for self and family (ii) Composite Transfer and packing grant (CTG) (iii) Reimbursement of charges on transportation of personal effects (iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

(i) **Travel Entitlements**

Travel entitlements as prescribed for tour/transfer in Para 2 above, except for International Travel, will be applicable in case of journeys on retirement. The general conditions of admissibility prescribed in S.R. 147 will, however, continue to be applicable.

(ii) **Composite Transfer Grant(CTG)**

- (a) The Composite Transfer Grant shall be paid at the rate of 80% of the last month's basic pay in case of those employees, who on retirement, settled down at places other than last station(s) of their duty located at a distance of or more than 20 km. However, in case of settlement to and from the Island territories of Andaman, Nicobar & Lakshadweep, CTG shall be paid at the rate of 100% of last month's basic pay. Further, NPA and MSP shall not be included as part of basic pay while determining entitlement for CTG. The transfer incidentals and road mileage for journeys between the residence and the railway station/bus stand, etc., at the old and new station, are already subsumed in the composite transfer grant and will not be separately admissible.
- (b) As in the case of serving employees, Government servants who, on retirement, settle at the last station of duty itself or within a distance of less than 20 kms may be paid one third of the CTG subject to the condition that a change of residence is actually involved.

(iii) **Transportation of Personal Effects :-** Same as Para 3(iii) above.

(iv) **Transportation of Conveyance :-** Same as Para 3(iv) above.

The general conditions of admissibility of TA on Retirement as prescribed in S.R. 147 will, however, continue to be applicable.

\*\*\*\*\*

9

L-11025/4/2021-Jus.I  
Government of India  
Department of Justice  
Justice-I  
\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 11<sup>th</sup> March, 2021

To,  
The Registrar (Judicial),  
Orissa High Court,  
Cuttack.

Subject: - Clarification regarding drawal of Composite Transfer Grant on  
Transfer/Retirement Journey of Hon'ble Chief Justice/Judges of High Courts.

Sir,

I am directed to refer to Registry of Orissa High Court's letter No. 684 III  
39/2011 dated 28.1.2021 on the subject mentioned above and to clarify that the  
Hon'ble Chief Justices/Judges of High Courts are entitled to 80% of the last  
month's basic pay towards Composite Transfer Grant in case of journey on  
transfer involving a change of station located at a distance of more than 20 Kms  
from each other, in accordance with Govt. of India, Ministry of Finance,  
Department of Expenditure's O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017  
(Annexure dated 10.07.2017).

2. In cases of transfer to Stations which are at a distance of less than 20  
Kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the  
composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is  
actually involved.

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR  
23 MAR 2021  
469  
Recd No.....  
Receipt Clerk  
High Court Jabalpur

Yours faithfully,

*Manish Kumar*

(Manish Kumar)

Under Secretary to Government of India  
Tel. No. 23782465.

Copy to:-

1. The Chief Secretaries of all States, Govt. of NCT of Delhi, UT of Chandigarh, UT of J&K and UT of Ladakh.
2. The Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. The Registrar General, all High Courts.
4. The Accountant General, All States/UT of Chandigarh, J&K and Ladakh.
5. The Pay & Account Officer, Supreme Court of India, New Delhi.
6. The Pay & Account Officer No. XIX, Govt. of NCT of Delhi, Fire Station Building, Shankar Road, New Delhi.
7. Guard Files/ Spare copies.
8. NIC, DoJ for uploading on website.

DAIC  
MAM  
2305

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक B/2065/  
चार-12-3/50


जबलपुर, दिनांक 5/04/2021

(Government of India, Department of Justice, Justice-I, New Delhi का पत्र क्रमांक L-11017/4/2021-Jus.I दिनांक 11.03.2021 की छायाप्रति)

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस.,
- 2- समस्त माननीय न्यायाधिपति महोदय के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर,
- 3- रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- 4- प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर,
- 5- रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- 6- ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- 7- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- 8- डिप्टी कंट्रोलर (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर,
- 9- असिस्टेंट रजिस्ट्रार (लेखा)/सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (यात्रा भत्ता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- ✓ 10- आई.टी. विंग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित किया जावे ?

  
( यू.एस. दुबे )  
ओ.एस.डी.-कम-पीपीएस